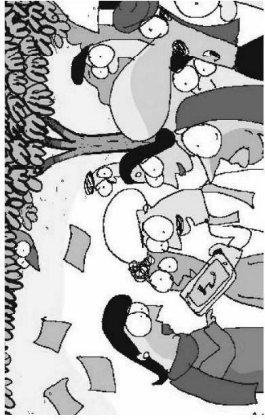


मनरेगा मजदूरों के खातों को आधार से जोड़ने का अभियान

मनरेगा स्कीम में हो रहे गड़बड़झालों को रोकने के लिए होगा आधार का इस्तेमाल, देशभर में 10 सितंबर तक लगाए जाएंगे कैंप



सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) से जुड़े सभी मजदूरों को आधार के दायरे में लाने के लिए अभियान शुरू कर रही है। इसका मकसद इस स्कीम के तहत गड़बड़ियों और डूप्लिकेशन को रोकना है। वित्त मंत्रालय के साथ सलाह कर ग्रामीण विकास मंत्रालय गांवों में कैंप लगाकर इससे लाभार्थियों से उनके बैंक खाते को आधार से लिंक करने के लिए उनकी सहमति मांगेगा।

एक सीनियर अधिकारी ने ईटी को बताया, 'आधार को लिंक करने से लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर होने में गड़बड़ी का कम करने में मदद मिलेगी...वायो-मीट्रिक वीरिफिकेशन यह प्रकटा करता है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे।' ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस अभियान के लिए 13 बैंकों और इंजीनियर

बैंक्स एसोसिएशन को तैयार किया है। अब तक नरेगा के तहत 10.7 करोड़ मजदूरों में से 50 फीसदी ने आधार के साथ अपना बैंक एकाउंट लिंक कराया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक और सीनियर अधिकारी ने बताया, 'हमने जहां 85 फीसदी वर्कर्स के लिए आधार सूचना इकट्ठा की थी, वहीं बैंक पहले इसकी सहमति चाहते हैं।'

देशभर में 25 जुलाई से 10 सितंबर के बीच ये कैंप आयोजित किए जाएंगे। कैंप के दौरान लाभार्थियों से सहमति फॉर्म होसिल करने के लिए सरकार ने बैंकों, नरेगा अधिकारियों से तब प्रक्रिया को अगाने को कहा है।

इसके साथ ही, बड़े सफाई अभियान के तहत सरकार नरेगा के तहत फर्जी और इन्वैलिड जांच कार्ड को हटाने का काम कर रही है। फर्जी पाए जाने के बाद तकरीबन 1.12 करोड़ जांच

कार्ड को हटाया जा चुका है। इनमें से 10 लाख वर्कर्स अब नरेगा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में दिलचस्पी नहीं रखते और उन्होंने अपना जांच कार्ड सरकार को सौंहर कर दिया है।

अंश-जुलाई के दौरान इस स्कीम के तहत 80 फीसदी पेमेंट समग्र पर किया गया है। फेब्रुअरी में देश इस स्कीम की एक बड़ी कमी मानती जाती है। इस साल ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस स्कीम के लिए राज्यों को अग्रेल में 23,443 करोड़ रुपये जारी किए थे, ताकि फंड की दिस्कल्ट नहीं हो। यह खम कुल बजट के आवंटन का आधा हिस्सा है। राज्यों को इस बावत बाकी राकम भी सितंबर में ऑडिट रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मिलने की उम्मीद है। सभी राज्यों में लाभार्थियों के खातों में डेपॉजिट फंड ट्रान्सफर के लिए मंत्रालय को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (एनईएफएमएस) का दायरा बढ़ाने की कहा गया है।